बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर
वर्ग – 5

26 फाल्गुन, 1938 (श.)

शुक्रवार, तिथि ----------

17 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 18

1.	शिक्षा विभाग	....	....	17
2.	खनन एवं भूतत्व विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**18**

रिक्त पदों पर बहाली

अ* 134. **श्री गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या मदरसा बोर्ड एवं मदरसों में नियुक्ति एवं शासी निकाय के गठन के लिए कोई नियमावली है;

(ख) क्या विभिन्न मदरसों में नियुक्ति प्रक्रिया में इस नियमावली का पालन किया जाता है;

(ग) वर्तमान में विभिन्न मदरसों में कुल कितने पद रिक्त हैं तथा सरकार इन रिक्त पदों पर कबतक बहाली करना चाहती है ?

राशि का गबन

* 222. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पीपराकोठी प्रखंड के मध्य विद्यालयों में डेस्क-बेंच क्रय में सरकारी राशि की व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई। मानक के विपरीत स्थानीय दुकानदारों से निम्न गुणवत्ता के बेंच-डेस्क की खरीदारी कर फर्जी बिल बनाया गया एवं सरकारी राशि का गबन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पीपराकोठी प्रखंड के मध्य विद्यालय, सूर्यपुर, पंडितपुर, टिकैता, यूएमएस मठिया, बरियारपुर, बभनौलिया, ढेकहॉ बेला, अखरा, अखरा कॉलोनी, मुर्दाचक, मधुछपरा, सेमरा, बेलबतिया व यूएमएस गोविंदापुर डेस्क-बेंच के क्रय में सरकारी राशि की बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है जिसकी जांच प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अशोक पासवान द्वारा की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त जिला के पीपराकोठी प्रखंड के उक्त विद्यालयों में डेस्क-बेंच की क्रय में सरकारी राशि का गबन कराकर जांच रिपोर्ट को प्रकाशित कर गबन करने वालों पर क्या सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अ* दिनांक 7 मार्च, 2017 ई. से स्थगित।

वेतन भुगतान कबतक

***** 223. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य से सम्बद्धता प्राप्त वित्त रहित इंटर कॉलेजों एवं डिग्री कॉलेजों का वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अनुदान की राशि जांच के नाम पर रोक रखी गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि सभी संबद्धता प्राप्त वित्तरहित इंटर कॉलेजकर्मी चाहे शिक्षक हों या शिक्षकेतर कमिर्यों को वेतन/अनुदान स्वीकृति के बाद ही मिलता है जिसका मापदंड इंटर कॉलेज एवं डिग्री कालेजों के परीक्षाफल से होता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो राज्य के सभी संबद्धता प्राप्त इंटर कॉलेजों/डिग्री कॉलेजों के कर्मी को भुखमरी से बचाने के लिए उनके वेतन का भुगतान करने पर सरकार विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

परीक्षा कबतक

***** 224. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के दर्जनों अंगीभूत इकाई के कॉलेज हैं जिनमें कई हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सत्र 2 साल देरी से चल रहा है जिसके कारण हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका है;

(ग) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के इस रवैये से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में काफी आक्रोश व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के बारे में क्या सोच रही है एवं विगत सत्रों की

परीक्षा लेकर कबतक उनके भविष्य को अग्रसारित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पुस्तकों का वितरण नहीं

***** 225. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार स्टेट बुक कॉरपोरेशन को पिछले 7-8 वर्षों में एक अरब 4 करोड़ 51 लाख रुपये पेनाल्टी देनी पड़ी है, स्कूलों में समय पर पुस्तकों का वितरण नहीं होने एवं पुस्तकों की गुणवत्ता बेहतर नहीं होना, इसका कारण रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 में क्रमश: विलंब पेनाल्टी के रूप में 15407297/-, 76896170/-, 52385590 तथा 61715422/- देना पड़ा है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पुस्तकों का वितरण करता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' एवं 'ख' में वर्णित आरोप पर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करना चाहती है, कितने दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, यदि नहीं तो क्यों ?

मॉडल मदरसा का रूप

***** 226. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं अररिया में एक-एक मदरसा को मॉडल बनाने एवं पूर्णिया में बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन चयनित मदरसों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जायेगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या चयनित मदरसा मॉडल मदरसा के रूप में कार्य करने लगेगा, यदि हां तो कबतक ?

प्रधानाचार्यों का स्थानांतरण

***** 227. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजकीयकृत उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की संचिका माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दस दिनों में उपस्थापित करने हेतु निर्देश के बाद भी जून, 2016 से अभी तक उपस्थापित नहीं की गई है जबकि इस संचिका के माध्यम से पूर्व में सैंकड़ों स्थानांतरण किए जाते रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्ति के कगार पर कार्यरत प्रधानाध्यापकों का ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होने से उनके मनोबल में गिरावट आई है साथ ही शिक्षकों को दी गई सुविधा में कमी आई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विभागीय मंत्री के आदेश की अवहेलना करनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को यथाशीघ्र दंडित करते हुए प्रधानाचार्यों को पूर्व में दी गई सुविधा के अनुरूप लंबित ऐच्छिक स्थानांतरण निश्चित समय सीमा के अंदर करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष कबतक

***** 228. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षा समिति का चुनाव करके विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से गांवों में काफी गुटबाजी और विभेद बढ़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय स्वशासन के तहत निर्वाचित वार्ड पार्षद्, पंचायत समिति और जिला पार्षद् स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए इन्हीं निर्वाचित सदस्यों को विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाये जाने से यह विभेद और गुटबाजी दूर हो सकती है और गांवों का माहौल तनावरहित हो सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गांवों में सद्भाव का माहौल पैदा करने हेतु उक्त जनप्रतिनिधियों को ही विद्यालय प्रबंध समितियों में अध्यक्ष बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान

* 229. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान लागू किये जाने के बावजूद इन शिक्षकों को विभागीय उदासीनता के कारण नया वेतन भुगतान नहीं हो सका है;

(ख) क्या यह सही है कि उन शिक्षकों को वेतन से छः-छः महीने तक वंचित रहना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है और दूसरों का मोहताज होना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उन शिक्षकों को माह के प्रथम सप्ताह में नये वेतनमान देने सहित नये वेतनमान लागू होने की तिथि से बकाया वेतन देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सरकारी धन की बंदरबांट

* 230. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर साल बड़ा बजट दिया जाता है, ताकि बिहार की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके;

(ख) क्या यह सही है कि इसके तहत वर्ष 2016 में प्रगति पत्रक और मूल्यांकन पंजी के मुद्रण के लिए बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड ने 9 करोड़ का बजट बिना किसी ओपेन टेंडर के 20 चहेते मुद्रकों को बांट दिया;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार वित्तीय नियमावली के नियम के अनुसार 25 लाख रुपये से अधिक के कार्य के लिए निविदा कराना आवश्यक है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार वित्तीय नियमावली के खिलाफ सरकारी धन की बंदरबांट करनेवाले दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विवाद का निराकरण

***** 231. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य के अनुदानित उच्च विद्यालयों/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के विवाद एवं समस्याओं के निराकरण हेतु एवं स्वतंत्र प्राधिकार के गठन का निर्णय लिया था;

(ख) क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों के विवाद और समस्याओं के लिए प्राधिकार का गठन हो चुका है किन्तु अनुदानित उच्च विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के विवाद के निराकरण के लिए अभी तक कोई प्राधिकार का गठन नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए गठित प्राधिकार को ही अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों के विवाद के निराकरण के लिए भी दायित्व सौंपना चाहती है?

मदरसा तालीमुल इस्लाम का निर्माण

***** 232. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के विस्फी अंतर्गत बरदाहा गांव में खेती की जमीन पर मदरसा तालीमुल इस्लाम का निर्माण सिर्फ कागजी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन के खाता संख्या-535 के अंतर्गत खेसरा संख्या-64 में कुल जमीन की माप 2 कट्ठा एक धुर है, जबकि फर्जीवाड़े के तहत बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को उक्त भूमि की माप 5 कट्ठा दिखाई गई है;

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक 29 जून, 2013 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी ने फर्जी ढंग से अपने स्थलीय जांच प्रतिवेदन में उक्त फर्जी मदरसा में 6 कमरों की संख्या, 12 कुर्सी-टेबुल की संख्या तथा पदस्थापित 6 शिक्षकों के 2015-16 में वेतन मद में 234000/- (दो लाख चौंतीस हजार) भुगतान हेतु स्वीकृति की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कागज पर निर्माण किए गए उक्त मदरसा से संबंधित सभी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बालू उत्खनन का पट्टा

***** 233. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय स्थित किउल नदी से निकाला हुआ बालू लखीसराय सहित बेगूसराय एवं समस्तीपुर तक उपयोग में लाया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि लगभग एक साल से लखीसराय के बालू उत्खनन का पट्टा का आवंटन नहीं होने के कारण बालू का उत्खनन एवं आपूर्ति बंद है;

(ग) क्या यह सही है कि बालू के उत्खनन एवं आपूर्ति बंद होने के कारण बेगूसराय एवं आसपास के इलाके को शेखपुरा एवं जमुई के बालू पर निर्भर होना पड़ रहा है जिसके कारण महंगे दर से बालू मिल रहा है और इसका असर आवास बनाने वाले एवं सरकारी योजनाओं पर पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त बालू खदान से बालू उत्खनन एवं आपूर्ति शुरू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक।

(ख) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

(ग) उत्तर अस्वीकारात्मक।
बेगूसराय एवं आसपास के इलाकों में बालू की आपूर्ति निकट के बंदोबस्त जिलों यथा - पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा आदि के बालूघाटों से किये जाने की सूचना है।

(घ) लखीसराय एवं जमुई (एक एकीकृत इकाई की बंदोबस्ती दिनांक 16.07.16 को सम्पन्न हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.12 को पारित न्यायादेश एवं बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में खनन कार्य आरंभ करने के पूर्व खनन योजना की स्वीकृति एवं पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बंदोबस्तधारी को प्रक्रिया पूरी होने पर अविलम्ब कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा, ताकि बालू खनन एवं आपूर्ति यथाशीघ्र प्रारम्भ हो सके।

उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद

***** 234. **मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि उर्दू टीईटी की परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर गलत होने एवं कई प्रश्नों के उत्तर हटा देने के कारण काफी संख्या में छात्र प्रभावित हुए;

(ख) क्या यह सही है कि उर्दू शिक्षकों के प्रथम चरण की नियुक्ति के बाद बहुत सारे पद रिक्त रह गए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्दू टीईटी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को ग्रेस अंक देकर उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद भरना चाहेगी, यदि हां तो कबतक?

रात्रि प्रहरी की नियुक्ति

***** 235. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के राजकीय/राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों की आधारभूत संरचना काफी समृद्ध की गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालयों में कम्प्यूटर, जेनरेटर, विज्ञान की प्रयोगशाला से संबंधित सामग्री, पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था की गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कोटि के विद्यालयों में कम्प्यूटर, जेनरेटर आदि की चोरी की घटनायें लगातार बढ़ रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' के विद्यालयों के भवन के रखरखाव एवं चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सभी विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विश्वविद्यालय भवन चालू कबतक

***** 236. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के आरा कतिरा में वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय है;

(ख) क्या यह सही है कि आरा जीरो माइल के पास वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय की अपनी जमीन है और नूतन परिसर में बी.एड. और प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन का मकान बना हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 में माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी के द्वारा बी.एड. भवन का उद्घाटन भी किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार विधिवत बी.एड. का वर्ग संचालन और कार्यालय का संचालन जीरो माइल, आरा में वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय भवन में चालू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भवन निर्माण कबतक

***** 237**. श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत प्रखंड एकमा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, परसा पूर्वी का भवन जर्जर हो गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विद्यालय में जर्जर भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रोफेसर की नियुक्ति

***** 238. **श्री रणविजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत राजापुर, कोईलवर में मच्चा जनता हाई स्कूल प्लस टू का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में अभी तक प्लस टू हेतु प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाना चाहती है कि मच्चा जनता हाई स्कूल, कोईलवर, भोजपुर में प्रोफेसर की नियुक्ति कबतक की जाएगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 17 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्